भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4560

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए अवसंरचना बांड को प्रोत्साहित करना

†4560. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए अवसंरचना बांड जारी करने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बांडों के माध्यम से शहरी अवसंरचना को वित्तपोषित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं या नीतियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं कि अवसंरचना बांडों से प्राप्त आय को किफायती आवास, जलापूर्ति और परिवहन जैसी महत्वपूर्ण शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कुशलतापूर्वक आवंटित किया जाए;

(घ) क्या सरकार ने अवसंरचना बांडों के निवेशकों को कोई कर प्रोत्साहन या अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने पर विचार किया है ताकि उन्हें अधिक आकर्षक बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पूर्व में शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए अवसंरचना बांडों के कार्यान्वयन में कोई विशिष्ट सफलता मिली या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): 25 जून 2015 को शुरू किए गए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में शहरों की क्रेडिट रेटिंग और फ्लोटिंग म्यूनिसिपल बॉन्ड सहित विभिन्न श्रेणियों में सुधार एजेंडा निर्धारित किया गया है। 483 शहरों के लिए क्रेडिट रेटिंग का कार्य सौंपा जा चुका

है और 468 शहरों में इसे पूरा किया जा चुका है। 468 शहरों में से 162 को निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग (आईजीआर) अर्थात बी - और उससे ऊपर की रेटिंग मिली है, साथ ही 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 34 शहरों को ए - और उससे ऊपर की रेटिंग मिली है।

01 अक्टूबर 2021 को शुरू किए गए अमृत 2.0 का उद्देश्य टियर-2 शहरों (जनसंख्या 50,000 से 99,999) की क्रेडिट रेटिंग और अमृत शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्रेडिट योग्यता को बढ़ाना है। अमृत 2.0 के तहत म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन को जारी रखा गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यूएलबी को म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए 13 करोड़ प्रति 100 करोड़ रु. मूल्य के बॉन्ड की दर से प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है, जिसमें प्रति यूएलबी अधिकतम 26 करोड़ रु. का प्रोत्साहन है। दूसरी बार पात्रता केवल ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए है, जिसमें जारी किए गए 100 करोड़ रु. मूल्य के बॉन्ड पर 10 करोड़ रु. प्रोत्साहन की दर है, जो अधिकतम 20 करोड़ रु. तक है।

आम तौर पर, शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए म्यूनिसिपल बांड जारी किए जाते हैं। अब तक, 13 यूएलबी अर्थात् अहमदाबाद (म्यूनिसिपल बांड और ग्रीन बांड), अमरावती, भोपाल, गाजियाबाद (ग्रीन बांड), हैदराबाद, इंदौर (म्यूनिसिपल बांड और ग्रीन बांड), लखनऊ, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, राजकोट, सूरत, वडोदरा (म्यूनिसिपल बांड और ग्रीन बांड) और विशाखापत्तनम द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए म्यूनिसिपल बांड और ग्रीन बांड जारी करके 4,984 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं और प्रोत्साहन के रूप में 331.83 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जुटाए गए म्यूनिसिपल बांड और जारी किए गए प्रोत्साहन का शहर/यूएलबी-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

अमृत 2.0 के तहत, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए आवंटन के 10% की परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अब तक 6,816.64 करोड़ रुपये की लागत वाली 22 पीपीपी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, बजट 2025-26 में, सरकार ने बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के संवर्धन/उन्नयन/पुनर्निर्माण और सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रु. का शहरी चुनौती कोष स्थापित करने की घोषणा की है। यह कोष बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक इस शर्त के साथ वित्तपोषित करेगा कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से वित्तपोषित किया जाए। बाजार वित्त तक पहुँच बनाने के लिए बहुत से यूएलबी के वित्तीय प्रबंधन और क्रेडिट रेटिंग में सुधार की आवश्यकता है।

"शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड को प्रोत्साहित करना" विषय में दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4560 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अमृत शहरों द्वारा जारी म्यूनिसिपल बांड की स्थिति

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	क्रेडिट रेटिंग	जुटाई गई धनराशि (करोड़ में)	जारी प्रोत्साहन राशि (करोड़ में)
1	अमरावती	एए-	2,000	26
2	ग्रेटर विजाग	एए	80	10.4
3	अहमदाबाद	एए+	200	26
4	सूरत	एए+	200	26
5	वडोदरा	एए+	100	13
6	भोपाल	एए	175	22.75
7	इंदौर	एए+	140	18.18
8	पुणे	एए+	200	26
9	ग्रेटर हैदराबाद	एए	495	26
10	लखनऊ	एए	200	26
11	गाजियाबाद (ग्रीन बांड)	एए	150	19.5
12	इंदौर (ग्रीन बांड)	एए+	244	20
13	पिंपरी चिंचवाड़	एए+	400	26
14	अहमदाबाद (ग्रीन बांड)	एए+	200	20
15	वडोदरा (ग्रीन बांड)	एए+	100	13
16	राजकोट	एए	100	13
	कुल		**4,984**	**331.83**

*****